रणजीत टाइम्स

इंदौर
गुरुवार , 19 मार्च , 2026
वर्ष 02 | अंक 72 कुल पृष्ठ : 8 | Digital
RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

शुभता, शुचिता व शक्ति की आराधना का पर्व

गुड़ी पड़वा

(प्रथम नवरात्रि मां शैलपुत्री की होगी आराधना)

वन्दे वाञ्छितलाभाय
चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं
यशस्विनीम्॥

भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस लूनार कैलेंडर के अनुसार भारतीय नव वर्ष के रूप में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी के नौ रूपों का पूजन व साधना की जाती है वस्तुत: यह सभी स्वरूप स्वयं आदिशक्ति द्वारा समय व आवश्यकतानुसार धारण किए गए। स्वयं आदिशक्ति श्री माताजी निर्मला देवी जी ने अपनी अमृतवाणी में इसका उल्लेख किया है देवी नौ बार पृथ्वी पर आईं, देवी ने उन सभी लोगों से युद्ध किया जो साधकों का विनाश कर रहे थे तथा उनका जीवन दूभर कर रहे थे। सताए हुए इन महात्माओं ने देवी से प्रार्थना की, उन्होंने भगवती की पूजा की और देवी नौ बार आवश्यकतानुसार अवतरित हुईं।

नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री, श्री आदिशक्ति का प्रथम अवतरण मानी जातीं हैं क्योंकि इससे पूर्व श्री आदिशक्ति सुरभि गाय के रूप में अवतरित हुई थीं। उन्होंने हिमालय में जन्म लिया था इसलिए उन्हें शैलपुत्री (हिमालय की पुत्री) कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस भारत के कुछ भागों में गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है महाराष्ट्र मैं विशेष तौर पर इसे भव्य रुप में आयोजित किया जाता है श्री माताजी ने गुड़ी पड़वा का वर्णन अपनी अमृतवाणी में इस प्रकार किया है कि, यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह नए साल का दिन है।... इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन वे एक छोटे से झंडे के साथ एक छड़ी पर एक छोटा घड़ा डालते हैं। घड़ा कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुड़ी पड़वा कुंडलिनी शक्ति की मात्र प्रतीकात्मक पूजा ना करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को साक्षात जागृत करने का प्रयत्न करें। श्री माता जी के सानिध्य में कुंडलिनी जागरण द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर कुंडलिनी शक्ति की चैतन्य लहरियों का आनंद सम अनुभव करें। कुंडलिनी जागरण द्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने टोल फ्री नम्बर 18002700800 पर सम्पर्क करें।

सोमनाथ से चीन सीमा तक बनेगा हाइवे

CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

सिंहस्थ
2028 तैयारियां

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए कई विकास कार्यों की सौगात दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश चहुंओर प्रगति कर रहा है और मध्य प्रदेश इस विकास यात्रा में हर कदम पर भारत सरकार के साथ है।

इसी वजह से सिंहस्थ को देखते हुए सरकार ने उज्जैन को 664 करोड़ रुपए की सौगात दी है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन को बदनावर से 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाइवे की सौगात दी है. दिल्ली जाने के लिए देवास-इंदौर के पास से सीधे गरोठ हाइवे भी मिला है. इसके अलावा 3839 करोड़ लागत का नेशनल हाइवे गुजरात के द्वारका से असम में चीन सीमा तक बनेगा. यह एनएच गुजरात के सोमनाथ और उज्जैन के महाकाल को सीधे जोड़ेगा।

गीता भवन के निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजनउज्जैन में 77 करोड़ से अधिक लागत के गीता भवन निर्माण के लिए भी भूमि-पूजन किया गया है. प्रदेश में विकास का क्रम जारी है. प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भगवन, गांवों में आदर्श ग्राम, वृंदावन ग्राम बनाए जा रहे हैं. किसान कल्याण वर्ष में उल्लेखनीय कार्यमुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं. पशुपालन विभाग ने सवा साल में 25 प्रशितक दूध उत्पादन बढ़ाया है. किसानों को 5 से 8 रुपए लीटर अधिक मूल्य का लाभ मिला है।

बच्चों को स्कूल में फ्री में मिलेंगे दूध के पैकेटप्रदेश में सांदीपनि विद्यालय, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जरूरी बदलाव किए गए हैं. स्कूली बच्चों को साइकिलें, ड्रेस, किताबें निःशुल्क वितरित की जा रही हैं. टॉपर बच्चों को स्कूटी, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप की सौगात मिल रही है. अब प्रदेश के बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क दूध के पैकेट मिलेंगे. इसके लिए माता यशोदा के नाम से नई योजना की शुरुआत की गई है।

सिंहस्थ विकास कार्यों के लिए 3600 करोड़ के प्रावधान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के मद्देनजर 13.50 करोड़ से अधिक के विकास कार्य जारी हैं. इसके साथ ही वर्ष 2026-27 में 3600 करोड़ के कार्यों के लिए नए प्रावधान किए हैं. उन्होंने कहा कि भगवान मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में लगभग 664 करोड़ के अलग-अलग कार्यों में नए मार्ग, विक्रम आरओबी, सड़क चौड़ीकरण, नए सीसी रोड भी शामिल हैं।

विधानसभा चुनाव

ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दाव

52 महिला विधायकों को मैदान में उतारा; इन बड़े चेहरों का काट दिया टिकट

बंगाल में 294 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसी बीच टीएमसी ने 294 सीटों में से 291 पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों की सूची में बड़ा दांव खेला है। टीएमसी ने अपनी लिस्ट में 52 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

वहीं टीएमसी की सूची में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। पार्टी ने मौजूदा 74 विधायकों का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने इन विधायकों का एंटी-इनकंबेंसी के चलते टिकट काटना बताया है। टिकट से वंचित नेताओं में मनोज तिवारी, विवेक गुप्ता, सावित्री मित्रा, रत्ना डे नाग, परेश पाल और कंचन मलिक जैसे नाम शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय जमीनी स्तर पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता को कई निर्वाचन क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर को लेकर चिंताएं थीं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर दक्षिण कोलकाता की अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी से होगा। सुवेंदु ने ममता को 2021 में नंदीग्राम से चुनाव हराया था। इस बार भवानीपुर सीट खास चर्चा में है, क्योंकि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है।

भवानीपुर में होगा दिलचस्प मुकाबला

भवानीपुर सीट पर मुकाबला जरूरी पर दिलचस्प माना जा रहा है। 2021 में ममता बनर्जी ने यहां 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कई नगर वार्डों में भाजपा की बढ़त ने मुकाबला को कड़ा बना दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने पहले ही बूथ स्तर के नेताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुनावी तैयारियों का मुद्दा लेना शुरू कर दिया है, खासकर मतदाता सूची में हुए मतदाताओं को ध्यान में रखा।

खास रपट | **राजमार्ग**

के बाद राजमार्ग संपर्क में सबसे बड़ा बदलाव होगा. इसका असर भारत के हर कोने में दिखाई देगा.

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे लंबी सुरंगों से होकर शिवालिक पर्वतमाला से गुजरता है (देखें: आखिरकार मंजिल तक), जबकि दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तर–पश्चिम के बीच लॉजिस्टिक्स के लिहाज से धुरी बन रहा है. अहमदाबाद प्रस्तावित औद्योगिक शहर धोलेरा के और करीब आ जाएगा. वहीं, बेंगलूरू और चेन्नै के बीच यात्रा आधे दिन के बजाय महज चार घंटे में पूरी की जा सकेगी. वाया बठिंडा अमृतसर से जामनगर की दूरी घटने से ऊर्जा, बंदरगाह और रिफाइनरी केंद्र करीब आ जाएंगे. तीव्र गति के साथ लखनऊ–कानपुर मार्ग की दूरी 30–45 मिनट में तय हो सकेगी. दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे खुलने पर अमृतसर दिल्ली से केवल चार घंटे और कटरा छह घंटे की दूरी पर होगा—पहले 13 घंटे की यह यात्रा खासी थका देने वाली होती थी. गुरुग्राम–पटौदी राजमार्ग द्वारका एक्सप्रेसवे तक सीधी पहुंच देगा, जिससे एनसीआर के सबसे व्यस्त यातायात मार्गों में से एक के आसपास कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी.

फायदे का सौदा

आइआइएम बंगलौर की तरफ से 2025 में सरकार के आदेश पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारतमाला परियोजना की वजह से लॉजिस्टिक्स में सुधार, माल ढुलाई लागत में कमी, परिवारों की आय और खर्च करने की क्षमता में वृद्धि जैसे फायदे पहले ही नजर आने लगे हैं. इसके साथ ही बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर हुई है.

जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था में बदलाव भी दिखने लगे हैं. अहमदाबाद के निर्यातक अब धोलेरा तक दो घंटे के बजाय एक घंटे में पहुंच सकते हैं. माल ढुलाई कंपनियां अमृतसर–जामनगर कॉरिडोर के आसपास अपने मार्ग फिर से निर्धारित कर रही हैं ताकि ईंधन पर खर्च घटे और माल की आवाजाही भी कम समय में हो सके. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं, ''दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे न केवल दोनों शहरों के बीच आवाजाही में तेजी लाएगा, बल्कि औद्योगिक केंद्रों को भी जोड़ेगा. गति शक्ति लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिलेगी और गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में विकास रफ्तार पकड़ेगा.'' इसी तरह, बेंगलूरू–चेन्नै एक्सप्रेसवे (जिससे चार घंटे में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकेगा) से भारत के दो सबसे बड़े महानगरों के बीच आवागमन, विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं और सप्ताहांत यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है. परिवहन नियोजन सलाहकार राजीव सक्सेना कहते हैं, ''यदि आप किसी बड़े शहर और पास के कस्बे के बीच की यात्रा का समय दो घंटे से कम कर सकते हैं, तो आप प्रभावी रूप से शहर की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर देते हैं. कस्बा महानगर का विस्तार बन जाता है, जो शहरी आवास और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का एक महत्वपूर्ण समाधान प्रदान करता है.''

रिपोर्ट कार्ड

₹5.35
लाख करोड़
34,800 किलोमीटर राजमार्गों को कवर करने वाली भारतमाला परियोजना की कुल लागत

21,783
किलोमीटर
जनवरी तक बन चुके राजमार्गों की लंबाई. यह कुल आवंटित 26,425 किमी का 82 फीसद

643
प्रोजेक्ट
जिनकी लागत 4 लाख करोड़ रुपए है, देरी से चल रहे

133
प्रोजेक्ट
जिनकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए है, अभी तक शुरू नहीं हुए

> **"दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे न केवल इन दो शहरों को बल्कि औद्योगिक केंद्रों को भी तेजी से आपस में जोड़ेगा, गति शक्ति लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा और गुजरात, राजस्थान समेत महाराष्ट्र में विकास को तेजी देगा."**
>
> **नितिन गडकरी,**
> *केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री*

इस आशावाद की झलक यातायात और राजस्व पूर्वानुमानों में दिखती है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आइसीआरए के मुताबिक, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और प्रतिकूल प्रभाव घटने से वित्त वर्ष 2026 में वाहनों की आवाजाही में वृद्धि वित्त वर्ष 2025 के करीब 2.5 फीसद से बढ़कर 4–5 फीसद होने की उम्मीद है. आइसीआरए का कहना है, ''इससे वित्त वर्ष 2026 में टोल वसूली में 5–9 फीसद की वृद्धि हो सकती है जबकि 2025 में यह करीब 6 फीसद रही थी.'' ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एसोसिएशन (एआइटीडब्लूए) के जे.पी. सिंह का कहना है कि माल ढुलाई में बचा हर घंटा कमाई के बराबर है. उनके मुताबिक, ''यात्रा जल्द पूरी होना, कम डीजल खपत, महीने में अधिक फेरे...यह वेतन वृद्धि ही तो है.''

देरी की कीमत

हालांकि, व्यापक परिदृश्य अब भी जटिल बना हुआ है. सरकार का कहना है कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए की 643 परियोजनाएं अभी निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं. 260 से ज्यादा परियोजनाओं में तीन साल तक की देरी हुई है और 80 परियोजनाओं में तीन साल से ज्यादा का विलंब. लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 133 अन्य परियोजनाओं के ठेके दिए जा चुके हैं लेकिन उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है. राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और जम्मू–कश्मीर में भारतमाला सड़कों का लगभग 40 फीसद काम पूरा हो चुका है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में यह आंकड़ा करीब 65 फीसद है. गुजरात और महाराष्ट्र में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाएं चल रही हैं.

सरकार की राजमार्ग परियोजनाओं के केंद्र में रहा 1,386 किलोमीटर लंबा दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पिछले साल अक्तूबर तक पूरा होने की उम्मीद थी. 2025 के अंत तक इस परियोजना की लागत 71,718 करोड़ रुपए थी, जो भारतीय इतिहास में सड़कों के मामले में सबसे ज्यादा है. संसद में गडकरी ने स्वीकारा कि भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, अनुमतियों में देरी और जटिल शहरी इंटरफेस के कारण उनका मंत्रालय इस परियोजना में देरी का

आखिरकार मंजिल तक

वर्षों से अटके कुछ प्रमुख राजमार्ग कॉरिडोर वित्त वर्ष 2027 तक पूरे होने जा रहे

अमृतसर बाइपास (4)
● 50 ● 38 ● 0
मई 2026*

व्यास-मेहता-बटाला-डेरा-बाबा नानक (4)
● 79 ● 30 ● 0
दिसंबर 2026*

अबोहर-फाजिल्का बाइपास (4)
● 45 ● 12 ● 0
अप्रैल 2026*

चंडीगढ़-अंबाला-शामली (6)
● 184
● 132 ● 31
दिसंबर 2026*

पनियाला-बड़ौदामेव (6)
● 87 ● 0 ● 0
सितंबर 2026*

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली-वडोदरा हिस्सा (8)
● 912 ● 900 ● 697
मार्च 2026*

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का वडोदरा-मुंबई हिस्सा (8)
● 450 ● 336 ● 180
मार्च 2027*

इंदौर-हैदराबाद (4)
● 527 ● 469 ● 375
दिसंबर 2026*

मोहाली-सरहिंद-सहना (4)
● 135 ● 22 ● 0
दिसंबर 2026* *आवंटित 27 किमी भाग के लिए*

अंबाला रिंग रोड (4)
● 23 ● 14 ● 0
सितंबर 2026*

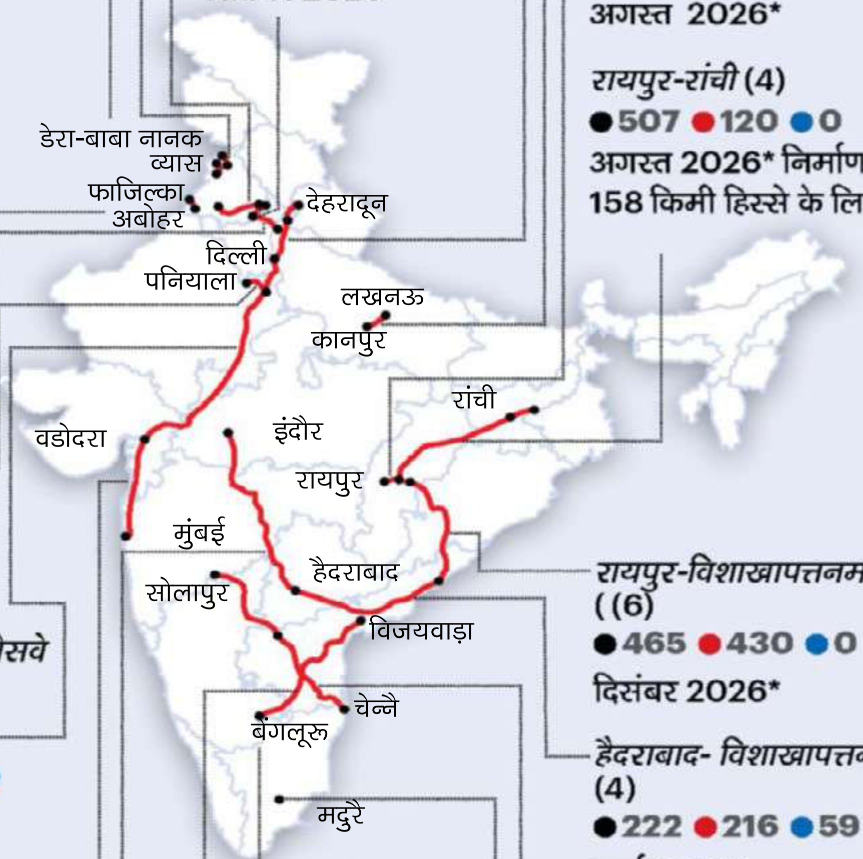

बेंगलूरु रिंग रोड (6)
● 280 ● 128
● 80
मार्च 2026*

बेंगलूरु-कडप्पा-विजयवाड़ा (6)
● 343 ● 176 ● 0
फरवरी 2027*

दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून 6)
● 264 ● 252 ● 48
जनवरी 2026* मुख्य कैरिजवे (212 किमी) और जून 2026 हरिद्वार स्पर (51 किमी) की डेडलाइन

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे (6)
● 63 ● 62 ● 0
मार्च 2026*

दुर्ग-रायपुर-आरंग ((4)
● 92 ● 58 ● 0
अगस्त 2026*

रायपुर-रांची (4)
● 507 ● 120 ● 0
अगस्त 2026* निर्माणाधीन 158 किमी हिस्से के लिए

रायपुर-विशाखापत्तनम ((6)
● 465 ● 430 ● 0
दिसंबर 2026*

हैदराबाद- विशाखापत्तनम (4)
● 222 ● 216 ● 59
मार्च 2026*

सोलापुर-कुर्नूल-चेन्नै (4)
● 290 ● 212 ● 0
अक्तूबर 2026*

मदुरै रिंग रोड (4)
● 30 ● 28 ● 0
अप्रैल 2026*

● कुल लंबाई (किमी) ● निर्मित लंबाई (किमी) ● यातायात के लिए खोला जा चुका (किमी);
* पूरा होने की समय-सीमा; लेन की संख्या ( ) में; आंकड़े निकटतम पूर्णांक में

सामना कर रहा है. ऐसी चुनौतियां कई अन्य राजमार्ग परियोजनाओं के सामने भी हैं.

दूर की जा रहीं कमियां

गडकरी इन बाधाओं को सिस्टम से जुड़ा बताते हैं. उनके मुताबिक, इसके लिए ''व्यवस्था को ठीक करना होगा.'' पिछले कुछ वर्षों में नियंत्रण मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं. अप्रैल 2024 में 150 से ज्यादा परियोजनाएं तीन साल से ज्यादा विलंबित थीं. दिसंबर 2025 तक यह संख्या घटकर 90 से कम हो गई. इसी तरह, ऐसी स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या भी आधी रह गई है जिनमें काम शुरू करने की तिथि का इंतजार हो रहा था. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य में तेजी आई है. दिल्ली में डीएनडी जंक्शन से जैतपुर तक 9 किलोमीटर लंबे खंड पर 95 फीसद काम पूरा हो चुका है और इसके जून तक पूरा होने की उम्मीद है. सोहना-दौसा-लालसोट जैसे लंबे खंड पहले से ही चालू हैं. इस एक्सप्रेसवे के कारण गुरुग्राम से जयपुर की यात्रा अब मात्र तीन घंटे में पूरी हो जाती है.

अधिकारियों की राय में बदलाव का श्रेय पर्दे के पीछे चल रहे व्यवस्थागत बदलावों को जाता है. भूमि अधिग्रहण को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) पर आधारित भूमि राशि नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है. सामान्य वित्तीय नियमों की मंजूरी के बाद 'परिवेश ऐप' वन संबंधी मंजूरी प्रक्रिया तेज कर देता है. रेलवे ओवरब्रिज संबंधी स्वीकृतियां अब ऑनलाइन दी जाती हैं, जिसमें अक्सर खासा समय बर्बाद हो जाता था. स्थानीय स्तर पर अटकी परियोजनाओं को मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य स्तरीय बैठकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और अगर इससे समस्या हल नहीं होती तो परियोजना निगरानी समूह या प्रधानमंत्री के प्रगति (सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन) प्लेटफॉर्म को भेजा जाता है. अब अनुबंधों को और सख्त बनाया जा रहा है. डिजाइन संबंधी खामियों पर ज्यादा सख्ती से जुर्माना लगाया जाता है. लगातार विलंबित परियोजनाओं के लिए फिर से निविदा जारी की जाती है. इस तरह के उपायों से काफी फायदा हुआ है.

हालांकि, कई हिस्सों में अंतिम चरण की आम समस्याएं अब भी कायम हैं. सीमावर्ती इलाकों में जमीन तक पहुंच, उपयोग में बदलाव, डिजाइन में आखिरी चरण में बदलाव और ठेकेदारों में कार्यकुशलता का अभाव अब भी प्रगति में बाधक है. गडकरी काम न करने वाले अधिकारियों और सलाहकारों की कड़ी आलोचना करते हैं. एआइटीडब्ल्यूए के जे.पी. सिंह एक और समस्या की ओर इशारा करते हैं, ''ऊंची टोल दरें लागत बढ़ाती हैं. भारत में ये सबसे ज्यादा हैं. यही नहीं, कई राज्यों की सीमाओं पर अनधिकृत 'टोल' वसूली होती है, और कई बार ट्रक चालक जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर ठेकेदारों का कहीं अता-पता नहीं होता.''

अगर ये एक्सप्रेसवे व्यापक स्तर पर निर्धारित समय पर खुल गए तो भारतमाला के अगले चरण का आधार मजबूत करने वाले साबित होंगे और हरित औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का रास्ता खोलेंगे. इससे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनावों के दौरान राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है. वहीं, यह भी पता चलेगा कि क्या भारत के सड़क निर्माण तंत्र ने आखिरकार अपने शुरू किए काम पूरा करना सीख लिया है या नहीं.■

आवरण कथा बांग्लादेश

हालांकि वे देश से दूर थे लेकिन राजनीति से कभी दूर नहीं हुए. हसीना सरकार ने अलग-अलग मामलों में उन्हें दोषी ठहराया. वे 2026 के आम चुनाव में बीएनपी का अभियान खुद संभालने के लिए करीब 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे. वापसी के कुछ ही समय बाद उनकी बीमार मां का इंतकाल हो गया. अब उन्होंने बीएनपी गठबंधन को जबरदस्त जीत दिलाई है. बांग्लादेश की संसद की 300 में से 212 सीटें उनके खाते में गई हैं. यह साफ दो-तिहाई बहुमत है.

रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद विदेशी मेहमानों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे, जिन्हें भारत के प्रतिनिधित्व के लिए भेजा गया था. ऐसे वक्त में जब यूनुस की अगुआई वाली अंतरिम सरकार के दौरान भारत-बांग्लादेश रिश्ते रसातल में जा पहुंचे थे, बिरला का वहां होना खास मायने रखता था. यह इशारा भी था कि बीते मतभेद नई सरकार के साथ रिश्तों पर हावी नहीं होंगे. एक जानकार ने साफ कहा, ''बड़ा संदेश यही था कि भारत उस सरकार के साथ बातचीत और काम करने को तैयार है, जिसे अब जनता का पूरा जनादेश मिला है.'' रहमान के औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर 'शानदार जीत' की बधाई दी. इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ''दो करीबी पड़ोसी और गहरे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़े देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए मैं भारत की प्रतिबद्धता दोहराता हूं.''

भारत के लिए हाल में हुए बांग्लादेश चुनाव के नतीजों में कई सकारात्मक बातें हैं. यह नतीजा एक स्थिर जनादेश दिखाता है, जिसे काफी हद तक बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं ने आगे बढ़ाया है. द *डेली स्टार* के संपादक और जाने-माने कॉलमिस्ट महफूज अनम कहते हैं, ''इस चुनाव ने बांग्लादेश को खतरनाक अनिश्चितताओं से बचा लिया है. वह राजनैतिक हो, आर्थिक हो या वैचारिक.'' वे यह भी कहते हैं, ''लोगों ने एक मध्यमार्गी बांग्लादेश के पक्ष में वोट दिया है, न कि कट्टर सोच वाले देश के लिए. धार्मिक वोट में बढ़ोतरी जरूर दिखी है, लेकिन संदेश साफ है. जनता चाहती है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक कानूनों के तहत चले.

> **रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया कि भारत बीते विवादों को नई सरकार के साथ रिश्तों पर हावी नहीं होने देगा.**

पुराने तनाव

एक स्थिर बांग्लादेश भारत के लिए अच्छी खबर ही है, खासकर इसलिए क्योंकि चुनाव अभियान के दौरान न तो कोई भारत विरोधी हैशटैग चला और न ही भारत विरोधी बयानबाजी हुई. अगस्त 2024 में जेन ज़ी की अगुआई में हुए विद्रोह ने शेख हसीना के 15 साल से ज्यादा लंबे शासन का अंत कर दिया था. उन्हें भारत भागना पड़ा और देश अनिश्चितता की खाई में चला गया. इसके साथ ही हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के बीच जो मजबूत रिश्ते बने थे, उनका भी अंत हो गया. अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार की भूमिका संभालने वाले यूनुस ने, एक भारतीय बांग्लादेश विशेषज्ञ के मुताबिक, ''भारत को

भारत-बांग्लादेश संबंध

तनातनी वाले मुद्दे

ढाका में नई सरकार के आने से भारत के पास अपने इस पड़ोसी के साथ पुराने विवाद सुलझाने का नया अवसर

प. बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ जवान

एएनआइ

अवैध प्रवासी ↑

अवैध तरीके से सीमा पार करने की समस्या बांग्लादेश बनने से पहले से चली आ रही है लेकिन केंद्र की मौजूदा फिक्र इस संकट को बढ़ाते रोहिंग्या शरणार्थी हैं. दशकों से सीमापार से आने वालों के कारण असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव हैं जिनके कारण जातीय तनाव पैदा हुआ. सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई की वजह से हुई मानवीय क्षति के कारण भारत विरोधी भावनाएं भड़क रही हैं. मई 2025 के बाद से भारत ने 2000 से ज्यादा बांग्लाभाषी प्रवासियों को वापस भेजा, जिस पर तीखी कानूनी और राजनैतिक प्रतिक्रिया हुई.

← घुसपैठ

भारत की बीएनपी सरकार से यही अपेक्षा होगी कि वह अतीत की गलतियां नहीं दोहराएगी और पूर्वोत्तर के उल्फा (असम) और एनएससीएन (नगालैंड) जैसे अलगाववादी संगठनों का दोबारा समर्थन नहीं करेगी. अवामी लीग सरकार ने वर्ष 2009 के बाद से सख्त कार्रवाई की और उल्फा नेताओं को गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर दिया. वार्ता के विरोधी उल्फा धड़े का नेता परेश बरुआ अब भी वहां म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर ठिकाना बनाए हुए है.

नदी जल बंटवारा

सीमा पर 54 जगहों पर छोटी-बड़ी जलधाराओं की आवाजाही में से दो नदियों गंगा और तीस्ता पर वर्षों से दोनों देशों के बीच तकरार चल रही है. तीस्ता को लेकर 1983 का जल-बंटवारा समझौता कभी आगे नहीं बढ़ा. पिछले महीने जब चीनी राजदूत याओ वेन ने एक अरब डॉलर की तीस्ता रिवर कॉम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट ऐंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का जायजा लेने संवेदनशील सिलिगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक रंगपुर का दौरा किया, तो यह भारत के लिए परेशान करने वाली बात थी. गंगा जल बंटवारे पर समझौते का दिसंबर 2026 (30 साल बाद) में नवीकरण होगा लेकिन फरक्का बराज को लेकर वार्ता जटिल और आरोप-प्रत्यारोप भरी होने के आसार हैं.

पश्चिम बंगाल में सेवाके के पास तीस्ता नदी

एएफपी

पाकिस्तान से नजदीकी

सन 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में आ रही गरमाहट नई दिल्ली के लिए बेचैनी का सबब है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री **शहबाज शरीफ** और बांग्लादेश के नेता **मोहम्मद यूनुस** के बीच मुलाकात समेत उच्चस्तरीय बैठकें हुईं, वह भी तब जब मई में पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव चरम पर था. एक और दुखदायी नुक्ता बांग्लादेश में और खासकर पश्चिम बंगाल के नजदीक पड़ने वाले जिलों में इस्लामी धड़े जमात-ए-इस्लामी का चुनावों में मजबूत होकर उभरना है. 1971 के बांग्लादेश युद्ध में यह पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है. भारत उम्मीद करेगा कि नई सरकार धनस्रोतों की जांच-पड़ताल के जरिए कट्टरपंथी गोलबंदी पर लगाम कसे और इस पार्टी को सुरक्षा नीतियों से दूर रखे.

एएनआइ

चीन फैक्टर

भारत नजर रखे है कि ढाका चीन के पैसे से बनने वाले बुनियादी ढांचे और जल परियोजनाओं का कैसे प्रबंधन करता है, खासकर वे जो **सिलिगुड़ी कॉरिडोर** सरीखे संवेदनशील इलाकों के करीब हैं. पारदर्शी कूटनीति के जरिए टकरावों को रोका जा सकता है और बांग्लादेश अपनी भागीदारियों को आगे बढ़ा सकता है. एक और चिंता की बात रक्षा और खासकर पनडुब्बियों और अहम बंदरगाहों को संभालने के मामले में बांग्लादेश की चीन पर बढ़ती निर्भरता है.

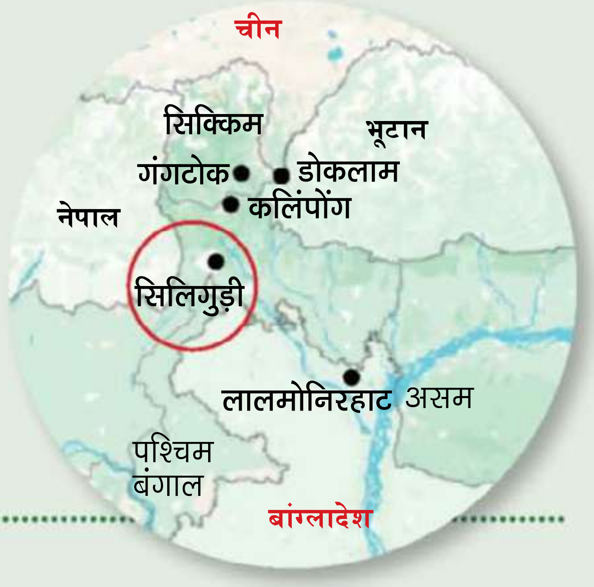

हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न

भारत ने यूनुस सरकार के दौर में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और राजनैतिक प्रतिनिधित्व न मिलने को लेकर लगातार ऐतराज जताए. हाल में एक मामला मैमनसिंह की कपड़ा फैक्ट्री के कामगार दीपूचंद्र दास की हत्या को लेकर आया उबाल था. उम्मीद है कि रहमान के राज में हालात में सुधार आएगा, जिसके संकेत उनके बार-बार समावेशन पर जोर देने और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री पद पर सम्मानित बड़े नेता निताई रॉय चौधरी की नियुक्ति से मिलता है.

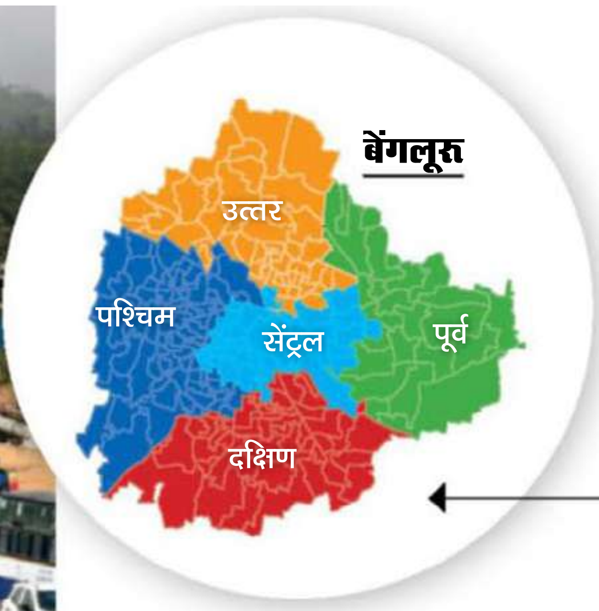

खास बातें

- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि वह लंबे समय से टलते आ रहे बेंगलूरू नगर निकाय के चुनाव 30 जून तक करवाए.
- चुनाव उन पांच नए निगमों के होंगे जो ‘भारी-भरकम’ बृहद बेंगलूरू महानगर पालिका की जगह बनाए गए हैं.
- भाजपा को बढ़त हासिल है क्योंकि नगरपालिका सीमा में आने वाले 27 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 में उसके विधायक हैं, जबकि 11 पर सत्तारूढ़ कांग्रेस का कब्जा.

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

कायापलट की कवायद

अदालत के फरमान पर हो रहे नगर निकाय चुनाव और राजकाज की नई व्यवस्थाओं से बेंगलूरू एक नई शहरी व्यवस्था के लिए तैयार

2012 में तीन हिस्सों में बांटा था जिन्हें एक दशक बाद फिर एक करना पड़ा.

खिंच गई तलवारें

पिछली परिषद का कार्यकाल 2020 में खत्म होने के बाद बेंगलूरू के निवासी बिगड़ते बुनियादी ढांचे को लेकर हताशा जताते रहे. बेंगलूरू की उत्तरी जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले लोगों में से एक अब्दुल वाजिद की राय में यह पुनर्गठन चुनौतियों के बावजूद संभावनाओं से भरा है. वे कहते हैं, ‘‘यह शुरुआत है. हमें नहीं पता आगे क्या होगा.’’

पार्टियां इसे ऊंचे दांव वाला मुकाबला मान रही हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जीबीए चुनाव की देखरेख का काम 20 जनवरी को पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और आरएसएस के दिग्गज नेता राम माधव को सौंपा. हाल ही बृहन्मुंबई नगर निगम में सत्ता पाने के बाद पार्टी ने एक और सुर्खियों में रहने वाली चुनावी जंग के लिए कमर कस ली है. माधव ने इसकी अहमियत को सामने रखते हुए एक्स पर लिखा कि यह चुनाव ‘विधानसभा की लड़ाई से कम नहीं’ होगा.

राज्य में सत्तासीन कांग्रेस ने 2025 के अंत तक उम्मीदवारों से आवेदन मंगवा लिए. उपमुख्यमंत्री और बेंगलूरू के विकास की देखरेख कर रहे डी.के. शिवकुमार ने भरोसा जताया कि पार्टी सभी पांचों निगम जीतेगी. फिर भी, भाजपा बढ़त में है. जीबीए के इलाके में पड़ने वाले 27 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 पर उसके विधायक हैं.

जनवरी में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों से पता चलता है कि 369 वार्डों में करीब 90 लाख मतदाता हैं. ये 2015 में हुए पिछले नगर निकाय चुनावों के दौरान मौजूद 198 वॉर्डों से करीब दोगुने हैं. बेंगलूरू में अपने पहले नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक पृथ्वी रेड्डी कहते हैं, ‘‘पहले वॉर्ड के आकार बेतुकी तादाद तक बढ़ गए थे. बाहरी छोर पर स्थित कुछ वॉर्ड में 80,000–90,000 लोग थे. यह विधानसभा क्षेत्र की तरह था. हम इसे मुद्दा आधारित बनाकर मतदाताओं को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं.’’

इस मुकाबले में इस बात की पड़ताल भी होगी कि क्या बेंगलूरू में नई सियासी शुरुआत नागरिक सुविधाओं का कायापलट कर सकती है.■

रणजीत टाइम्स
इंदौर, गुरुवार 19 मार्च 2026

सुर्खियां

▸ जलवायु परिवर्तन

सामना अब एक

भारतीय मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट 'वर्ष 2025 में भारत की जलवायु पर बयान' में कहा है कि किस तरह बीता वर्ष बढ़ते तापमान, कहीं कम कहीं ज्यादा बारिश और अतिशय मौसमी घटनाओं से भरा रहा. आखिर क्यों है यह हमारे लिए चिंता की बात

ग्राफिकः **नीलांजन दास/एआइ**
आलेख : **जुमाना शाह**

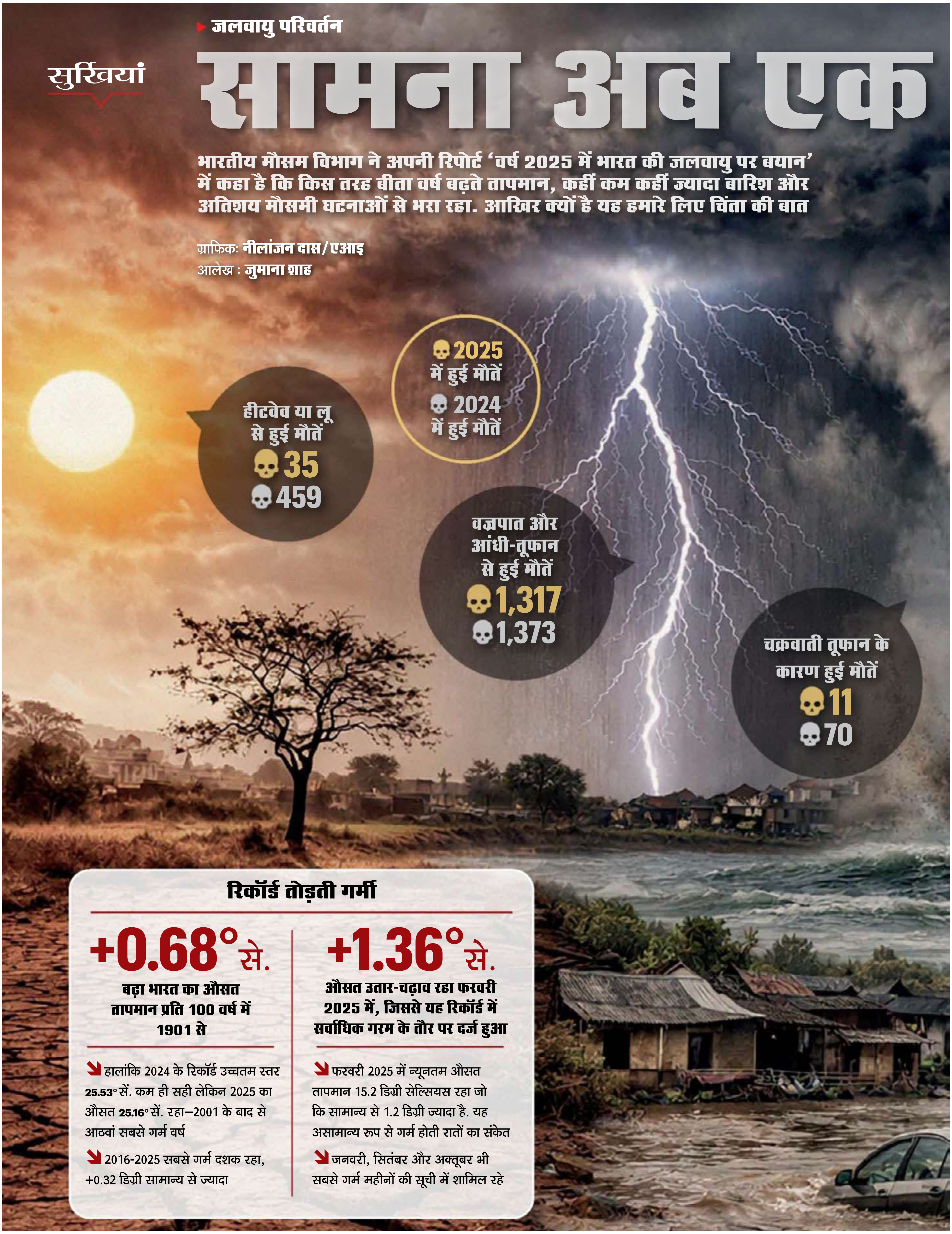

☠ 2025 में हुई मौतें
☠ 2024 में हुई मौतें

हीटवेव या लू से हुई मौतें
☠ 35
☠ 459

वज्रपात और आंधी-तूफान से हुई मौतें
☠ 1,317
☠ 1,373

चक्रवाती तूफान के कारण हुई मौतें
☠ 11
☠ 70

रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी

+0.68° से.

बढ़ा भारत का औसत तापमान प्रति 100 वर्ष में 1901 से

- हालांकि 2024 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर **25.53°** सें. कम ही सही लेकिन 2025 का औसत **25.16°** सें. रहा–2001 के बाद से आठवां सबसे गर्म वर्ष
- 2016-2025 सबसे गर्म दशक रहा, +0.32 डिग्री सामान्य से ज्यादा

+1.36° से.

औसत उतार-चढ़ाव रहा फरवरी 2025 में, जिससे यह रिकॉर्ड में सर्वाधिक गरम के तौर पर दर्ज हुआ

- फरवरी 2025 में न्यूनतम औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है. यह असामान्य रूप से गर्म होती रातों का संकेत
- जनवरी, सितंबर और अक्तूबर भी सबसे गर्म महीनों की सूची में शामिल रहे

नए मिजाज से

सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

वर्ष 2025 में अतिशय मौसमी घटनाओं से हुई मौतें

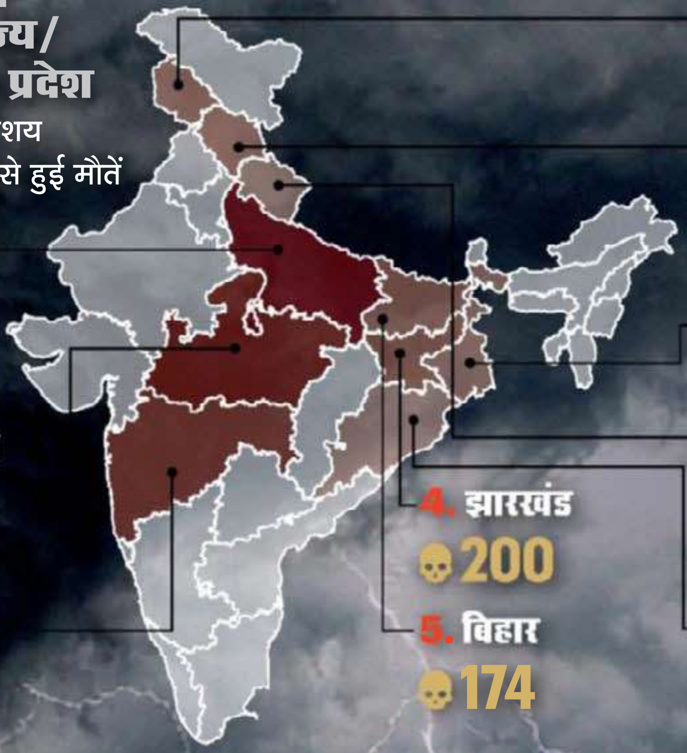

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मौतें
1. उत्तर प्रदेश	410
2. मध्य प्रदेश	350
3. महाराष्ट्र	270
4. झारखंड	200
5. बिहार	174
6. जम्मू-कश्मीर	168
7. हिमाचल प्रदेश	166
8. पश्चिम बंगाल	146
9. उत्तराखंड	117
10. ओडिशा	110

चरम मौसम से हुई मौतें

2,763

मौतें हुई चरम मौसमी घटनाओं के कारण वर्ष 2025 में जो वर्ष 2024 में हुई 3,201 मौतों से कम

भारी बारिश और बाढ़ से हुई मौतें

1,372
1,282

सामान्य से ज्यादा बारिश...

1,274 मिमी

हुई वर्ष 2025 में जो कि लंबी अवधि के औसत (एलपीए) के मुकाबले 110 फीसद ज्यादा

- 126.7 मिलीमीटर मई में हुई बारिश, 125 साल में इस महीने की सर्वाधिक
- मॉनसून (जून से सितंबर) में एलपीए या सामान्य से 108 फीसदी ज्यादा बारिश

... मॉनसून अब भी असमान क्षेत्रीय पैटर्न

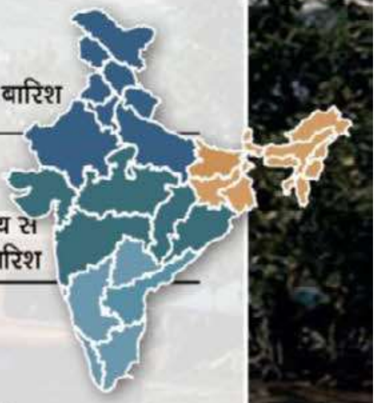

क्षेत्र		
■ उत्तर पश्चिम	127	ज्यादा बारिश
■ मध्य	115	ज्यादा बारिश
■ दक्षिण	110	सामान्य से ज्यादा बारिश
■ पूर्व और उत्तर पूर्व	80	कम बारिश

(आंकड़े लंबी अवधि (1971-2020) के औसत के % में हैं)